

प्रेषक,
विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

पंचायतीराज अनुभाग:

देहरादून

दिनांक 18 जून 2013

विषय:- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत विकास निधि मद हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-N- 11019/37/2013-BRGF, दिनांक 10.10.2013, पत्र संख्या- N-11019/37/2013-BRGF-(I) दिनांक 10.10.2013, पत्र संख्या-N- 11019/37/2013-BRGF(II) दिनांक 10.10.2013 तथा पत्र संख्या-N-11019/37/2013-BRGF (III) दिनांक 10.10.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत विकास मद हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु जनपद टिहरी का कुल अनुमोदित परिव्यय 1820 लाख के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत पत्र संख्या-N-11019/37/2013-BRGF (III) दिनांक 10.10.2013 द्वारा रु0 10.36 करोड़ सामान्य अंश में तथा पत्र संख्या-N- 11019/37/2013-BRGF (II) दिनांक 10.10.2013 द्वारा रु0 0.01 करोड़ अनुसूचित जनजाति अंश में पत्र संख्या- N-11019/37/ 2013-BRGF-(I) दिनांक 10.10.2013 द्वारा रु0 1.75 करोड़ अनुसूचित जाति अंश में अर्थात् कुल धनराशि रु. 12.12 करोड़ (रु. बारह करोड़ बारह लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखने की निम्न प्रतिबन्धों के अधीन श्री महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजना आयोग भारत सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिये निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3- उक्त आवंटित धनराशि को ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय, स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/मार्ग निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि की योजनावार आवंटन की सूचना शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायी जाय धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन, भारत सरकार एवं महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायें।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर शासन एवं योजना आयोग, भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2)

6- यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रौक्चोरमेन्ट रूल्स, 2008 तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों (योजना की गाइड लाईन्स) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित जनपद के कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक माह की 25 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही कार्य की प्रगति से समय समय पर शासन को अवगत कराया जाए।

8- बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर परचेज रूल्स, डी0जी0एस0एन0डी0 की दरें अथवा टेन्डर/ कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

9- वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अब तक की अवशेष राशि व वर्तमान में दी जा रही धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

10- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-01-केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्रपुरोनिधानित योजना-104-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि-42-अन्य व्यय से रु. 10.36 करोड़ (रु. दो करोड़ छत्तीस लाख मात्र), अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा केन्द्रपुरोनिधानित योजनायें -0101-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान-42-अन्य व्यय से रुपये 1.75 करोड़ (रु. एक करोड़ पच्चेतर लाख मात्र) तथा अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-00-796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना-11-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि-20-सहायक अनुदान/ अंशदान रुपये 0.01 करोड़ (रुपये एक लाख मात्र) की धनराशि सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-96(पी) दिनांक 14-11-2013 द्वारा प्राप्त निर्देशों अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद कोनिया)

सचिव।

(3)

संख्या 3304
(1) / XII / 2012 / 82(1) / 2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सँवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून/वित्त-1।
9. जिला पंचायतराज अधिकारी, जनपद टिहरी।
10. विभागीय पत्रावली/समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जि0एल0 शर्मा)
अनु सचिव।